(ख) क्या इन्हें मनमाने ढंग से ठेकेदारों और अन्य अनधिकृत छोटे ठेकेदारों को दे दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी नुकसान होता है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पहलू पर ध्यान दिया है और इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(घ) यदि नही, तो क्या सरकार उक्त राज्य में सर्वेक्षण करके कोयले के निक्षेपों का पता लगाने के लिए कदम उठायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नही ।

(ग) प्रश्न नही उठता है।

(घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1957 मे मध्य प्रदेश मे कोयला निक्षेपों का अवस्थापित करने के लिए यत्रस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय व्यधन द्वारा अन्वेषण किये जा रहे है । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पच और तावा घाटी पाथाखेड़ा, विश्रामपुर, सोनहाट, लखमपुर झिलिमिली, सोहागपुर, मोहपानी और सिंगरौली कोयला क्षत्रों के मार्गों के पट्टा मुक्त क्षेत्रों में व्यधन द्वारा अन्वेषण किए गए । झिलिमिली और मोहपानी में व्यधन सक्रियाए सम्पूरित हो गई हैं और उन्हें अन्य कोयला क्षेत्रो में जारी रखा जा रहा है । भारतीय खान ब्यूरो और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कोरबा और काम्पटी कोयला क्षेत्रों में विस्तृत व्यधन किया है, मध्य प्रदेश में अभी तक किए गए भूवैज्ञानिक मानचित्रण और व्यधन द्वारा लगभग 113,900 टन कोयले की कुल उपलभ्य राशियां अनमानित की गई हैं । आगे का कार्य प्रगति में है ।

राष्ट्रीय इंधन नीति

1412. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के विचाराधीन राष्ट्रीय इंधन नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है और

(ख) यदि हा, तो सरकार कब तक इस नीति का निर्धारण कर लेगी तथा नीति का निर्धारण किन आधारो पर किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख). सरकार ने, आगामी 15 वर्षों के दौरान अपनाए जाने वाले इंधन नीति की रूपरेखा सुझावित करने के लिए इधन नीति समिति नियुक्त की है। इस समिति ने अतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमे समिति को के लिए ही नीति दी गई है आशा की जती है कि समिति की तम रिपोर्ट मार्च, 1973 तक तयार होगी ।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, पटना का बंद होना

1413. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **भारी उद्योग** मत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ब्रिटानिया इजीनियरिग कपनी (वैगन डिविजन) बिहार के पटना जिलान्तर्गत मोकामा से कई वर्षों से काम करती आ रही है ,

(ख) क्या उक्त कपनी ने बिहार सरकार को कारखाना बद करने का नोटिस दिया है; यदि हा तो इसके क्या कारण है ।

(ग) क्या कंपनी को बंद करने के विरोध मे ब्रिटानिया इजीनियरिग लेबर यूनियन

नें प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । कंपनी ने बताया है कि कारखाने के कार्य परिणाम 1966-67 से अनुकूल नही रहे है, पर्याप्त क्षमता बेकार पडी है, इससे काफी हानि हुई है और बैगन यूनिट को चलाते रहने के लिए वित्तीय साधनो की पूर्ण कमी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अधीन ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी (बैगन डिवीजन), मोकामा के कार्यों की जांच करने के लिए जांच समिति गठित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

Closure of Factories in Gujarat due to shortage of Coke

1414. SHRI ARVIND M. PATEL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether several factories in Gujarat have been closed down due to the shortage of coke; and

(b) if so, the steps being taken by Government to supply sufficient coke to Gujarat to avoid such closure of industries in future?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUBODH HANSDA): (a) and (b). Some factories have shut down. The movement of coal and coke to different consumers all over the country was affected due to locking up of wagons due to the 'Mulki' rules agitation in December, 1972/January, 1973. The U. P. Engineers strike in January, 1973 had also upset the railway operation beyond Moghalsarai. U.P. Engineers' strike has, however, been called off and allotments for loading of coke/coal have been stepped up. As against an allotment of 551 wagons for loading of coke to Gujarat in December, 1972, 792 wagons were allotted in January, 1973.

Circulation of Leaflet in Hong Kong Levelling charges against Indian Commissioner

1416. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR:
SHRI H. M. PATEL:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have noticed a printed leaflet circulated by the Editor, "The Indian", Hong Kong levelling serious charges against the present Indian Commissioner in Hong Kong;

(b) if so, the reaction of Government to the charges contained therein; and

(c) whether Government have taken any action or propose to take any action in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH): (a) Yes, Sir, Government have received copies of the leaflet.

(b) and (c). Government have investigated the charges and have found them either exaggerated or based on some misunderstanding. However, in this case, as in every other case, whenever Government find scope for improvement of their Missions they take appropriate measures about it.

Payment of Minimum Wage to Bidi Workers in Tripura.

1417. SHRI BIREN DUTTA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Bidi workers of Tripura are not given minimum wage of Rs. 3.00 per day; and